

भारत को 'ग्रेट गेम' प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला करने के लिए मध्य एशिया की ओर अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा रविवार को बुलाई गई तीसरी भारत-मध्य एशिया वार्ता इस वर्ष नई दिल्ली द्वारा इस क्षेत्र से संपर्क बनाने की श्रृंखला में से एक है, जो कुछ हद तक अफगानिस्तान की घटनाओं से भी प्रेरित है।

सभी पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) के नेताओं के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली आने से एक महीने पहले और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों के साथ "क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद" के ठीक एक महीने बाद यह संवाद आयोजित किया गया है।

रविवार को अफगानिस्तान पर चर्चा जिन मुद्दों पर हुई उनमें अफगानिस्तान को "तत्काल" मानवीय सहायता प्रदान करना, व्यापार बढ़ाना और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल था। यह महत्वपूर्ण है कि मध्य एशियाई गणराज्यों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली आने का विकल्प चुना, यह एक संकेतक है कि मध्य एशिया में भारत की पहुँच, कई दशकों से साउथ ब्लॉक द्वारा उपेक्षित क्षेत्र को पारस्परिक रूप से बदला जा रहा है।

संयुक्त बयान, कि वे अफगानिस्तान पर "व्यापक क्षेत्रीय सहमति" साझा करते हैं, उपयुक्त है, यह देखते हुए कि भारत की तरह, अफगानिस्तान के सभी मध्य एशियाई पड़ोसी आतंकवाद, कट्टरता, नशीले पदार्थों और शरणार्थियों के खतरे के बारे में चिंतित हैं। हालांकि, भारत के विपरीत, अधिकांश मध्य एशियाई गणराज्य तालिबान शासन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं; उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने वहाँ मिशन फिर से खोल दिए हैं। भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार लंबे समय से 2 अरब डॉलर से कम रहा है और सभी पक्ष इसे बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसके अलावा, मध्य एशिया में परियोजनाओं के लिए भारत ने 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट, और चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन जैसी कनेक्टिविटी पहल सभी संवाद का हिस्सा थे।

जबकि भारत-मध्य एशिया संबंधों को मजबूत करना और उनके पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के पुनरुद्धार की बहुत आवश्यकता है, ऐसे प्रयासों को जटिल बनाने वाले भू-राजनीतिक क्रॉस-करंट को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। जबकि रूस का मध्य एशिया गणराज्य सरकारों पर प्रभाव जारी है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और 100 बिलियन डॉलर के व्यापार (कुछ अनुमानों के अनुसार) ने इसे इस क्षेत्र में एक केंद्रीय आंकड़ा बना दिया है।

अमेरिका भी इस क्षेत्र में पैर जमाने की मांग कर रहा है, खासकर अफगानिस्तान के बाद। इस बीच, मध्य एशिया के लिए भारत की भूमि संपर्क पाकिस्तान द्वारा बाधित है जो प्रत्येक मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ मजबूत संबंध और पारगमन व्यापार समझौते बना रहा है।

वैकल्पिक मार्ग, ईरान के चाबहार के माध्यम से, काबुल के तालिबान के अधिग्रहण के बाद एक झटका लगा है, और भारतीय-प्रबंधित शाहिद बेहेशती टर्मिनल के विकास को अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि भारत ने एशिया के अन्य हिस्सों के साथ संबंधों को मजबूत किया है, अब उसे मध्य एशिया की ओर अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा यदि उसे इस क्षेत्र में चल रहे 'ग्रेट गेम' प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला करना है, और उन देशों के साथ अपने साझा इतिहास को पुनः प्राप्त करना है। मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण बाजार है, ऊर्जा का एक स्रोत है, और उग्रवाद और कट्टरता के खतरों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- प्र. मध्य एशियाई गणराज्यों में सबसे उत्तर में कौन सा गणराज्य अवस्थित है?
- (a) कजाकिस्तान
(b) तुर्कमेनिस्तान
(c) तजाकिस्तान
(d) उज्बेकिस्तान

Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Which republic is located in the northernmost of the Central Asian republics?
- (a) Kazakhstan
(b) Turkmenistan
(c) Tajikistan
(d) Uzbekistan

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. भारत और मध्य एशिया गणराज्यों में आपसी सम्बन्धों के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं? भारत के लिए इन देशों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना क्यों आवश्यक है? (250 शब्द)
- Q. What are the different areas of mutual relations between India and the Republic of Central Asia? Why is it necessary for India to strengthen its position in these countries? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।